

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 322*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023/20 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया उर्वरकों पर राजसहायता

322*. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत चार वर्षों के दौरान देश में यूरिया उर्वरक की खरीद के लिए किसानों को वर्ष-वार कुल कितनी राजसहायता प्रदान की जा रही है;
- (ख) क्या सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राजसहायता में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यूक्रेन में युद्ध के कारण सरकार द्वारा देश में किसानों के लिए यूरिया और उर्वरक की निरंतर और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने यूरिया और अन्य उर्वरकों के घरेलू विनिर्माण में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री

(डा. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“यूरिया उर्वरकों पर राजसहायता” के संबंध में श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा पूछे गए दिनांक 11.08.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 322* में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): 'उर्वरकों में डीबीटी' प्रणाली के तहत, उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% राजसहायता जारी की जाती है, जो प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर आधारित होती है। पिछले चार वर्षों के दौरान यूरिया उर्वरकों पर संवितरित राजसहायता और यूरिया राजसहायता में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	यूरिया राजसहायता पर व्यय	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)
1	2019-20	57097.66	-
2	2020-21	93857.03	64.38
3	2021-22	104870.12	11.73
4	2022-23	168676.65	60.84

(ग) और (घ): रूस यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर उर्वरकों और इसके कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई। तथापि, भारत सरकार ने राजसहायता की मात्रा में वृद्धि करके उचित मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। 2021-22 में उर्वरक राजसहायता पर 1,57,640.09 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो 2022-23 में बढ़कर 2,54,798.93 करोड़ रुपये हो गए हैं। भारत सरकार ने उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक करारों और संयुक्त उद्यमों (जेवी) को भी सुकर बनाया है।

स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुकर बनाने तथा यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की थी। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 यूरिया इकाइयां नामतः पानागढ़, गड़ेपान में 2 नई और गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, रामागुंडम में पुनरुद्धार की गई 4 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिन्होंने देश की मौजूदा स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता में प्रति वर्ष कुल मिलाकर 76.2 एलएमटी की वृद्धि की है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अपने उद्देश्यों में से एक स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्य के साथ 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी शुरू की। देश की कुल यूरिया उत्पादन क्षमता 2017-18 की 207.54 एलएमटी से बढ़कर 2022-23 में 283.74 एलएमटी हो गई है।